pany has been directed to hand over stainless steel blades worth Rs. 48 lakhs and further to pay liquidated damages of Rs. 1.2 lakhs to State Trading Corporation of India Limited. The company has also been placed on the defaulters' list.

(b) and (c). No decision has been taken on the proposal of Sharpedge Limited to expand its annual production from 260 million blades to 450 million blades.

पैराशूट के लिए घटिया कपड़ा खरीदा जाना

3185. **श्री दया राम शाक्य:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियमों के अनुसार पैराशूट के लिए कपड़े को सी. आइ. ए. डी. आगरा द्वारा पास कराया जाना आवश्यक है और क्या पिछले 2-3 वर्षों के दौरान कानपूर की एक कोरियाई फर्म से पैराशूट के कपड़े की खरीद की गई थी और उसे सी. आई. टी. सी. कानपुर से पास कराया गया था, यदि हां, तो इस फर्म को इस कपड़े के लिए कितने मूल्य का आर्डर दिया गया था और उसे किस प्रकार इस्तेमाल किया गया था;

(ख) क्या कपड़े के घटिया होने का पता चलने के बावजूद इस फर्म से कपड़ा बदलने के लिए नहीं कहा गया तथा इसकी बजाय इस घटिया कपड़े के लिए पूरा भुगतान कर दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस फर्म तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Daily Wage Workers Serving with Western Base Workshop

3186. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that daily wage workers are serving with Western Base Workshop, 1326 Base depot, Western Store Division and 52 RCC for the last ten to twenty years continuously but they (the workers) have still not been declared regular/permanent; and

(b) if position stated at (a) above is correct, what steps are being taken to bring them on a regular/permanent roster?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) and (b). There are many daily-wage workers in these units and elsewhere, who have remained on muster-rolls for several years, not continuously but for a maximum period of six months at a time in accordance with departmental regulations. As regards "decasualisation" of their employment, the position has been explained in my D.O. letter No. 305/VIP/RRM/81(1), dated the 10th February, 1981 addressed to the Hon'ble Member, relevant extracts of which are laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-2083/81].

Casual Employees Working under Secretary, Border Roads Development Board

3187. SHRI DAYA RAM SHAKYA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state how many casual employees are working in the following units under the Secretary, Border Roads Development Board as skilled and unskilled and since when; and if they have completed 240 days, why they have not been brought on regular monthly wage;

(i) Western Store Division (GREF);

(ii) Western Base Workshop (GREF);

(iii) 1326 Base Depot (GREF);

(iv) Detachment of the 52 RCC (GREF)?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): The details are being collected.

Chinese Arms Aid to Pakistan

3188. PROF. AJIT KUMAR MEHTA:
SHRI CHANDRAJIT YADAV:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of China's supply to Pakistan T-59 medium, T-60 amphibious and T-62 light tanks in addition to unspecified number of MI-4 Hound helicopters and TU-16 and TU-4 medium bombers within the next three to five months;

(b) whether Government are also aware to the recent visit of Chinese military experts to Gilgit and Muzaffarabad in connection with Pakistan's air bases expansion in Pak occupied Kashmir and in the northern parts of Pakistan; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) and (b) Government have seen press reports to this effect but there is no reliable information to confirm them.

(c) The developments which have a bearing on our security are constantly monitored and their implications analysed for appropriate action to ensure full defence preparedness.

भारत में रह रहे युगांडा मूल के नागरिक

3189. **श्री तारिक अनवर:**
श्री हीरा लाल आर0 परमार:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भारत में रह रहे युगांडा मूल के नागरिकों की संख्या क्या है; और

(ख) वे किन किन शहरों में रह रहे हैं और वे किन-किन- व्यवसायों में लगे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) तथा (ख). चूंकि युगांडा राष्ट्रमंडलीय देश है, अत: युगांडा के राष्ट्रिकों चाहे वे भारतीय मूल के हों अथवा अन्यथा को भारत में प्रवेश करने और रहने के लिये वीसा अथवा आवासीय परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें निर्धारित प्राधिकारियों के पास स्वयं को दर्ज न कराने की छूट है। इसलिये उन शहरों जिनमें युगांडा के ऐसे राष्ट्रिक रह रहे हैं और जिन व्यवसायों में लगे हैं के बारे में सूचना संकलित नहीं की गई है।

सीमेन्ट का आयात

3190. **श्री निहाल सिंह:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर 1980 में प्रतिवर्ष 150 करोड़ के मूल्य के सीमेन्ट के आयात के अपने निर्णय की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने सीमेन्ट का आयात किया जाना है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ;

(ग) क्या सरकार के इस निर्णय का विरोध करने वाले कुछ संसद सदस्यों ने 12 दिसम्बर 1980 को प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री से यह मांग की थी कि प्रतिदिन 200 टन की उत्पादन क्षमता वाले 30 लघु सीमेन्ट संयंत्रों को जिनको वित्तीय बाधाओं के कारण सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सका था, देश के हित में फिर से चलाया जाये; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया है;

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चरणजीत चानना): (क) और (ख). चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सीमेन्ट का आयात किया जा